पूरी बेंच

माननीय मुख्य न्यायधीश श्री एस.एस. संधावालिया, सी.जे., माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.एस. तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरबंस लाल, के सामने हले।

मेजर सिंह,-याचिकाकर्ता,
बनाम
भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।
1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 2089।
10 अप्रैल 1980।

दंड प्रक्रिया संहिता (2 ऑफ 1974) अधिनियम (5 ऑफ 1978) द्वारा संशोधित - धारा 416, 432, 433, 433-ए और 434 - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14, 72 और 161, सूची की सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 4 सूची III की II और प्रविष्टियाँ 1 और 2 - धारा 433-ए कुछ मामलों में सजा की छूट और कटौती की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है - संसद - क्या ऐसा कानून बनाने में सक्षम है - धारा 433-ए के प्रावधान - क्या यह सीमित करता है अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा और इसलिए असंवैधानिक - धारा 416 के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायालय द्वारा मौत की सजा को कम किया जाना - दोषी को - क्या 14 साल की वास्तविक जेल अवधि पूरी होने से पहले रिहा किया जा सकता है - का कम किया जाना राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मौत की सजा - धारा 433-ए के प्रतिबंध - क्या ऐसे मामलों पर लागू होते हैं - धारा 433-ए - क्या इसके आवेदन में भेदभावपूर्ण है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान 1950 की सातवीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि 4 के मद्देनजर, राज्य विधानमंडल ऐसे मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम होगा, जहां एक दोषी को उसकी सजा भुगतने के लिए रखा जाना है और उसे कैसे रखना है; और यह नहीं कि उसे कितने समय तक रखा जाना है। किसी दोषी कैदी को जेल, सुधारगृह घोषित परिसर में कितने समय तक रखा जाना है। बोर्स्टल संस्था और इसी प्रकृति की अन्य संस्थाएं न्यायालय द्वारा उस पर लगाई गई सजा पर निर्भर होंगी, जो कि राज्यपाल या राज्य सरकार या राष्ट्रपति और केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती हैं, जैसा कि प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा परिकल्पित किया गया है। संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संहिता की धारा 432 और 433 के प्रावधानों के अलावा, न तो जेल मैनुअल और न ही जेल अधिनियम में कोई प्रावधान राज्य सरकार को किसी दोषी की सजा माफ करने की कोई शक्ति प्रदान करता है। 7वीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि II में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लेख स्पष्ट और विशिष्ट है क्योंकि यह संविधान के प्रारंभ में मौजूद थी। प्रविष्टि समवर्ती सूची में होने के कारण इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि संसद दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित नया

कानून बनाने या मौजूदा संहिता में संशोधन को प्रभावित करने के लिए सक्षम है। इसलिए, संसद संहिता की धारा 433 ए के प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है। (पैरा 12, 13 और 14)

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 432 और 433 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित शक्तियों का प्रक्षेपण नहीं हैं। संहिता की धारा 432 और 433 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं, और भले ही उपरोक्त दो अनुच्छेदों को संविधान से हटा दिया जाए, धारा 432 और 433 के प्रावधान, और उस मामले के लिए संहिता की धारा 434 को अवैध या असंवैधानिक नहीं बनाया जाएगा और राज्य सरकार या केंद्र सरकार उक्त प्रावधानों के आधार पर इसमें निवेश की गई शक्तियों का आनंद लेना जारी रखेगी। यदि संविधान के उपरोक्त प्रावधानों को संविधान से मिटा दिया जाता है, तो इसका परिणाम केवल भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति से उन शक्तियों को छीनना होगा जो वे अब उन प्रावधानों के आधार पर प्राप्त करते हैं। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्यपाल' या 'राष्ट्रपति' को 'राज्य सरकार' या 'संघ सरकार' अभिव्यक्ति के साथ परस्पर विनिमय नहीं किया जा सकता है और कोई भी 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति को नहीं पढ़ सकता है। अभिव्यक्ति 'राष्ट्रपति' के स्थान पर 'राज्यपाल' या 'केंद्र सरकार', इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 432, 433 और 434 के संदर्भ में राज्य या केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है। संहिता संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति में निहित शक्ति से उत्पन्न होती है। दोनों शक्तियां अलग-अलग हैं और अलग-अलग रहेंगी। अंतर, हालांकि कमजोर है, दो शक्तियों के प्रयोग में निहित है, जबकि किसी दिए गए मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग वैध रूप से किसी भी मंत्री या अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे इसके द्वारा बनाए गए व्यवसाय के नियमों के तहत सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत राज्यपाल इसे केवल राज्यपाल के नाम पर व्यक्त करते हैं, लेकिन राज्यपाल को मामले का कोई वास्तविक संदर्भ दिए बिना, लेकिन ऐसे मामले में जहां संविधान या क़ानून राज्यपाल या राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान करता है। तब मंत्रिपरिषद या मंत्री या व्यवसाय के नियमों के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कार्य करने के लिए अधिकृत अधिकारी को मामले पर अपनी सलाह के साथ राज्यपाल या राष्ट्रपति को विचार के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, तब भी जब राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि संहिता की धारा 433-ए संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के प्रावधानों पर आघात करती है। (पैरा 17, 20 एवं 24)

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि धारा 416 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा किया

गया परिवर्तन भी धारा 433-ए के प्रावधानों से प्रभावित होता है। संहिता की धारा 433-ए का पहला भाग उन मामलों को शामिल करता है जहां मौत की सजा वाले अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जहां तक अदालतों का सवाल है, उनका कार्य सज़ा देना है - वे एक सज़ा के स्थान पर दूसरी सज़ा दे सकते हैं। अदालतों द्वारा सजा का प्रतिस्थापन, भले ही इसे कम्यूटेशन के रूप में वर्णित किया गया हो, प्रतिस्थापित सजा को लागू करने के बराबर होगा और इसलिए, जब भी अदालतें धारा 416 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करती हैं, तो वे यह समझा जाना चाहिए कि किसी ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है जो मौत की सजा से दंडनीय है और तदनुसार एक दोषी का मामला जिसकी मौत की सजा को अदालत द्वारा संहिता की धारा 416 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, संहिता की धारा 433-ए प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के दायरे में आता है। (पैरा 28)

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 434 के अवलोकन से पता चलता है कि मौत की सजा के मामले में, केंद्र सरकार, भले ही वह 'उपयुक्त सरकार' न हो, के पास वही शक्तियां हैं जो राज्य सरकार को धारा 432 और 433 के तहत प्राप्त हैं। कोड। धारा 433-ए स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 432 और 433 के तहत प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की शक्ति के दायरे को प्रतिबंधित करती है और चूंकि धारा 434 के तहत केंद्र सरकार को उस शक्ति के बराबर शक्ति मिलती है जो धारा के तहत राज्य सरकार को प्राप्त है। - धारा 432 और 433, इसलिए धारा 434 के तहत इसकी शक्ति तदनुसार धारा 433-ए के प्रावधानों द्वारा सीमित कर दी गई है और इसलिए, ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देती है, दोषी कैदी को पहले रिहा नहीं किया जा सकता है उन्होंने 14 साल की वास्तविक जेल की सजा पूरी कर ली है। (पैरा 29)

अभिनिर्धारित किया गया कि भेदभाव का जो प्रश्न संभवतः उठ सकता है वह केवल उन मामलों से संबंधित है जहां किसी दोषी की मौत की सजा को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कम कर दिया जाता है, जबकि उन लोगों के खिलाफ जिनकी मौत की सजा को संहिता की धारा 433 या 434 या 416 के तहत कम कर दिया गया है। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 433-ए न तो कोई सीमा लगाती है और न ही संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित संवैधानिक शक्तियों पर कोई सीमा लगा सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप भेदभाव होगा। संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के विरुद्ध खड़ा करें। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तब होता है जब राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करता है। यहां ऐसा मामला नहीं है, जिन दोषियों की मौत की सजा को, जैसा भी मामला हो,

राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा बदल दिया जाता है, उनकी संवैधानिक शक्तियों का अंतिम प्रयोग उन लोगों के अलावा एक वर्ग से होता है जिनकी मौत की सजा को धारा 416, 432, 433 और संहिता के 434 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। अतः संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता। (पैरा 30, 31 और 32)

24 सितंबर, 1979 को माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया की माननीय खंडपीठ द्वारा इसमें शामिल कानून मामला के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधा-वालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति हरबंस लाल की बड़ी पीठ ने अंततः 10 अप्रैल, 1980 को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(i) राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता की रिहाई के मामले को रिट याचिका के पैरा 5 में उल्लिखित अपने नीतिगत निर्णय के अनुसार धारा 433-ए के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निपटाए, क्योंकि वे लागू नहीं हैं। उनके मामले में जैसा कि रिट याचिका के पैरा 11 में प्रस्तुत किया गया है।

(ii) वैकल्पिक रूप से 'संहिता' के 433-ए के प्रावधानों को रिट याचिका के पैरा 13 में उल्लिखित आधार पर अधिकारातीत मानते हुए रद्द कर दिया जाए और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 को उचित रिट के माध्यम से निर्देशित किया जाए। याचिकाकर्ता के मामले को पिछले नियमों/नीति के तहत निपटाने का आदेश या निर्देश जैसे कि विवादित धारा 433-ए कभी लागू ही नहीं हुई।

(iii) इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी ईथर रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने का आदेश दिया जाएगा।

(iv) इस बीच याचिकाकर्ता को अधिक हिरासत से बचने के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए क्योंकि वह 23 जून, 1979 को अपनी 10 साल की वास्तविक सजा पूरी कर लेगा।

(v) शपथ पत्र दाखिल करने/सत्यापन संलग्न करने की छूट दी जाए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील एस. वी. राठी के साथ वकील बलवंत सिंह मलिक।

प्रतिवादी की ओर से यू.ओ.आई. के वकील एस.एस. शेरगिल के साथ वकील कुलदीप सिंह।

जी.एस. ग्रेवाल, अतिरिक्त. ए.जी. पंजाब, पंजाब राज्य के लिए।

हरियाणा राज्य के लिए श्री एच.एस. गिल, एएजी के साथ यू.डी. गौड़, ए.जी.।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. एस. तेवतिया,

1. क्या 1978 के अधिनियम संख्या 45 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) में जोड़े गए धारा 433-ए के प्रावधान, या तो इस कारण से असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त हैं कि संसद नहीं थी इसे अधिनियमित करने के लिए सक्षम होना या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या इसके अनुप्रयोग में यह ऐसे भेदभाव को जन्म देता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा नापसंद किया जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन दो रिट याचिकाओं (सिविल रिट संख्या 2089 और 1979 की 2167) में निर्धारण के लिए उठता है।

2. श्री बलवंत सिंह मलिक ने अपनी दलीलों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जिस पर वर्तमान में ध्यान दिया जाएगा, 1979 के सिविल रिट संख्या 2089 में मेजर सिंह के मामले के तथ्यों को प्रासंगिकता में लाया है और इसलिए, अकेले इस मामले के तथ्य संदर्भित करने की आवश्यकता है।

3. 1979 की सिविल रिट संख्या 2089 में याचिकाकर्ता मेजर सिंह की प्रासंगिक समय में उम्र लगभग 2 वर्ष या उससे अधिक थी। उन्हें किसी अदालत द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई, जो उच्चतम न्यायालय तक कायम रही। वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत दया याचिका पर उसी सजा को एक सजा में बदलने में सफल रहे, उन्होंने 23 जून, 1979 को 10 साल की वास्तविक जेल अवधि पहले ही पूरी कर ली थी, जो कई छूट के साथ थी। आरयू में साल-दर-महीने आ गए, टीएन नीति यूसीजन ओई टीएन स्टेट यूओरियिनिएंट मैट ऐसे दोषी जो टीएनई तारीख ओई एमई कमीशन ओआई अपराध पर ज़ू वर्ष से कम उम्र के थे, और जिनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, हो रिहा किए जाने के बाद उन्हें 10 साल की वास्तविक जेल हिरासत (छूट को छोड़कर) से गुजरना होगा, बशर्ते कि उन्होंने पूरे जिले में अच्छा आचरण बनाए रखा हो। लेवल कमेटी ने मेजर सिंह की रिहाई के बारे में राज्य सरकार को सिफारिश की है। जेल महानिरीक्षक, पुनाजो पर आरोप है कि उन्होंने राज्य

सरकार को इसे अग्रेषित करते समय उक्त सिफारिश पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालाँकि, राज्य सरकार ने संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों के मद्देनजर रिहाई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जो तब तक 18 दिसंबर, 1978 से प्रभावी हो गया था।

4. राज्य की ओर से दायर रिटर्न में, याचिका से ऊपर दिए गए सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, इस तथ्य को छोड़कर कि जेल महानिरीक्षक ने राज्य सरकार के विचार के लिए सिफारिश भेज दी थी और इससे संबंधित अन्य तथ्य छूट सहित कुल कारावास की सजा भुगतना। इन दोनों तथ्यों के संबंध में कहा गया है कि कारा महानिरीक्षक ने संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों के मद्देनजर दोषी मेजर सिंह की रिहाई के लिए राज्य सरकार के विचारार्थ अनुशंसा को अग्रसारित नहीं किया, और यह कि याचिका में उल्लिखित 6 साल और 6 महीने के बजाय छूट की अवधि 6 साल, 3 महीने और 28 दिन हो गई और जब एक महीने और बारह दिनों की पैरोल अवधि को उसमें से घटा दिया जाता है, तो जेल की कुल अवधि भी शामिल हो जाती है। वास्तव में दोषी की उम्र 16 साल 2 महीने और 16 दिन हो गई। आगे यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने जेल की सजा की निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद विभिन्न प्रकार के दोषियों की सूची सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। ये निर्देश दोषियों को सजा की ऐसी किसी भी अवधि की समाप्ति पर रिहाई का कोई अधिकार नहीं देते।

5. संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ये निम्नलिखित शब्दों में हैं: -

"433-ए. कुछ मामलों में छूट या रूपांतरण की शक्तियों पर प्रतिबंध, -

> धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान की गई सजाओं में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को धारा 433 में आजीवन कारावास की धारा के अंतर्गत के तहत बदल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा न काट ली हो।''

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मलिक ने तर्क दिया है कि कानून के प्रयोजनों के लिए एक कैदी की रिहाई से संबंधित भारत के संविधान की अनुसूची मामला सातवीं की सूची II की प्रविष्टि 4 के प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी मामले की जांच और सुनवाई से

निपटने के लिए, वास्तव में, संहिता का सहारा लिया जाना चाहिए, एक बार जब आरोपी पर मुकदमा चलाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है और अदालत द्वारा लगाए गए कारावास की सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जाता है, तो यह जेल है अधिनियम और कैदी अधिनियम जो जेल में उसकी हिरासत और वहां से रिहाई को नियंत्रित करेगा और इस हद तक कि संहिता में कोई भी प्रावधान दोषी कैदी की रिहाई से संबंधित है, यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 पर लागू होता है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 में शामिल मामलों के संबंध में कानून राज्य विधायिका का विशेष विशेषाधिकार है, इसलिए समर्थक संसद कैदियों की रिहाई से संबंधित किसी भी प्रावधान को अधिनियमित करने में सक्षम नहीं होगी।

7. आगे यह तर्क दिया गया कि संविधान के प्रारंभ में संहिता में कुछ प्रावधानों का अस्तित्व इस तथ्य के लिए निर्णायक नहीं है कि क्या कैदियों की रिहाई सातवीं की सूची III की प्रविष्टि 2 में निपटाए गए मामले से संबंधित है। भारत के संविधान की अनुसूची. अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने जी. वी. रामनैय्या बनाम सेंट्रल जेल, राजमुंदरी के अधीक्षक और अन्य[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया।

8. उस मामले में उनके आधिपत्य के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए से 489-डी के तहत अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा माफ करने के लिए 'उपयुक्त सरकार' थी।

9. पुरानी संहिता की धारा 402(3) 'उपयुक्त सरकार' को इस प्रकार परिभाषित करती है: [नई संहिता की धारा 432(7) के बराबर]:

> "इस धारा में और धारा 401 में, अभिव्यक्ति 'उचित सरकार' का अर्थ होगा-
>
> (ए) ऐसे मामलों में जहां सजा किसी अपराध के लिए है, या धारा 401 की उप-धारा (4-ए) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के तहत पारित किया जाता है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार; और
>
> (बी) अन्य मामलों में, राज्य सरकार।

10. उस मामले में, सरकारिया, न्यायमूर्ति, जिन्होंने बेंच के लिए राय दी, ने माना कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 36 और 93 के मद्देनजर, मुद्रा, सिक्का और कानूनी मुद्रा, जो कि धाराओं के तहत अपराध हैं 489-ए से 489-डी, आई.पी.सी. संबंधित, वे मामले थे जो विशेष रूप से 'संघ विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते थे; इसलिए, धारा 489-ए से 489-डी के तहत अपराध उस मामले से संबंधित

[1] ए आई आर 1974 अस सी 31

अपराध थे जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित थी; और समवर्ती सूची की उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 1 को पढ़ने से पता चलता है कि आपराधिक कानून का दायरा पहले भारतीय दंड संहिता को शामिल करके बढ़ाया गया था, और उसके बाद, इस तरह के बढ़े हुए दायरे से कानूनों के खिलाफ सभी अपराध संबंधित थे। सूची I या सूची II में निर्दिष्ट किसी भी मामले को विशेष रूप से बाहर रखा गया था। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 36 और 93 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि संख्या I, सूची III में खंड को छोड़कर यह सभी प्रकार के संदेह से परे दिखाता है कि धारा 489-ए से 489-डी के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में, केवल केंद्र सरकार थी किसी दोषी की सज़ा को निलंबित करने या कम करने में सक्षम।

11. सूची III-समवर्ती सूची-की प्रविष्टि I और प्रविष्टि 2। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची निम्नलिखित शर्तों में हैं:

> "1. आपराधिक कानून, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं, लेकिन सूची I या सूची II में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों को छोड़कर और नौसेना, सैन्य या वायु सेना या किसी के उपयोग को छोड़कर। नागरिक शक्ति की सहायता में संघ के अन्य सशस्त्र बल।
>
> '2. आपराधिक प्रक्रिया, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं।"

दोनों प्रविष्टियों की तुलना से जी. वी. रामनैय्या के मामले (सुप्रा) और वर्तमान मामले के अनुपात की अनुपयुक्तता दिखाई देगी। प्रविष्टि 1 में किया गया बहिष्करण प्रविष्टि संख्या 2 में दोहराया नहीं गया है।

12. सूची II की प्रविष्टि 4 निम्नलिखित शब्दों में है:

> "4. जेलें, सुधारगृह, बोर्स्टल संस्थाएं और अन्य संस्थाएं समान प्रकृति की होती हैं और उनमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति; जेलों और अन्य संस्थानों के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।"

सूची II की प्रविष्टि 4 के मद्देनजर, हमारी राय में, राज्य विधानमंडल ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने में सक्षम होगा कि एक दोषी को उसकी सजा भुगतने के लिए कहां रखा जाना है, और उसे कैसे रखा जाना है; और यह नहीं कि उसे कितने समय तक रखा जाना है। एक दोषी कैदी को कितने समय तक जेल, सुधारगृह, बोर्स्टल संस्थान और इसी प्रकृति के अन्य संस्थानों के रूप में घोषित परिसर में रखा जाएगा, यह न्यायालय द्वारा उसे दी गई सजा पर निर्भर करेगा, जो कि छूट के अधीन हो सकता है। राज्यपाल या

राज्य सरकार या राष्ट्रपति और केंद्र सरकार द्वारा, जैसा कि संविधान और संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा परिकल्पित है, जो नीचे दिए गए हैं: -

संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद

> "72. (1) राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति होगी, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम करना, राहत देना या कम करना या उसकी सज़ा को निलंबित करना, कम करना या कम करना-
>
> (ए) * * * * *
>
> (बी) उन सभी मामलों में जहां सजा या सज़ा एक के लिए है किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ अपराध, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है;
>
> (सी) सभी मामलों में जहां सजा मौत की सजा है।
>
> (2) * * * * *
>
> (3) खंड (1) के उप-खंड (सी) में कुछ भी उस समय लागू किसी भी कानून के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली मौत की सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।
>
> * * * * *
>
> * * * * *
>
> * * * * *
>
> 161. किसी राज्य के राज्यपाल के पास उस मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी, जिसके लिए कार्यकारी शक्ति होगी राज्य का विस्तार है।"

संहिता की धारा 432, 433 और 434 के प्रासंगिक प्रावधान।

> "432. (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है, तो उपयुक्त सरकार, किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर, जिसे सजा पाने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है, उसकी सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या पूरी सजा या उसके कुछ हिस्से को माफ कर सकती है जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है।

* * * * *

"433. उपयुक्त सरकार, सजा पाए व्यक्ति की सहमति के बिना, सजा काट सकती है -

(ए) भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सजा के लिए मौत की सजा;

(बी) चौदह साल से अधिक की अवधि के लिए आजीवन कारावास या जुर्माने की सजा;

(सी) किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास के रूप में कठोर कारावास की सजा, जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी, या जुर्माना;

(डी) जुर्माने के साथ साधारण कारावास की सजा

434. मौत की सजा के मामले में राज्य को धारा 432 और 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

13. कानून का यह प्रस्ताव कि, संहिता की धारा 432 और 433 के प्रावधानों के अलावा, न तो जेल मैनुअल में और न ही जेल अधिनियम में कोई प्रावधान राज्य सरकार को किसी दोषी की सजा माफ करने की कोई शक्ति प्रदान करता है, अब नहीं है गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[2] और बाद में मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह और अन्य[3] में उनके आधिपत्य की आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर संदेह है, जिसमें उनके आधिपत्य ने निम्नलिखित का प्रतिपादन किया था प्रस्ताव: -

"(1) कि आजीवन कारावास की सजा छूट सहित 20 साल के अंत में स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होती है, क्योंकि विभिन्न जेल मैनुअल या जेल अधिनियम के तहत बनाए गए प्रशासनिक नियम भारतीय दंड संहिता के वैधानिक प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा का मतलब कैदी के पूरे जीवन की सजा है, जब तक कि उपयुक्त सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत पूरी सजा या आंशिक सजा माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग नहीं करती;

(2) उपयुक्त सरकार के पास सजा माफ करने या माफ करने से इनकार करने का निर्विवाद विवेक है और जहां वह सजा माफ करने से इनकार करती है, वहां

---

[2] ए आई आर 1961 अस सी 600

[3] ए आई आर 1976 अस सी 1552

राज्य सरकार को कैदी को रिहा करने का निर्देश देने वाली कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है;

* * * * *

14. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II-समवर्ती सूची- की प्रविष्टि 2 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लेख स्पष्ट और विशिष्ट है क्योंकि यह संविधान के प्रारंभ में मौजूद थी। प्रविष्टि समवर्ती सूची में होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि संसद आपराधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित नया कानून बनाने या मौजूदा आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने में सक्षम है।

15. उपरोक्त कारणों से हम मानते हैं कि संसद संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी।

16. श्री मलिक द्वारा प्रचारित अगला मुद्दा यह था कि संहिता की धारा 433-ए के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 द्वारा क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल में निवेश की गई शक्तियों को सीमित कर देंगे और, इसलिए, उक्त प्रावधान असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त हैं। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर जोर देते हुए अपनी उपरोक्त दलील को विस्तार से बताया कि संहिता की धारा 432, 433 और 434 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का अनुमान मात्र हैं, जो भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 161 और 72 के प्रावधान के आधार पर उनमें यह निहित है। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के लिए, विद्वान वकील ने के.एम. नानावटी बनाम बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र)[4] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन लेने की मांग की, और निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया: -

> "आइए अब इस विषय पर कानून की ओर मुड़ें जैसा कि 1898 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू होने के बाद से भारत में प्राप्त होता है, संहिता की धारा 401 कार्यपालिका को सजा के निष्पादन को निलंबित करने या पूरी या किसी भी सजा को माफ करने की शक्ति देती है। सज़ा का हिस्सा बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर जिसे सज़ा देने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है। धारा 402 कार्यपालिका को सजा पाने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने और अन्य सजाओं को कम कठोर प्रकृति की सजा में बदलने की शक्ति देती है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को महामहिम में निहित विशेषाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति सौंपी गई थी। धारा 401 की उपधारा (5) में यह भी प्रावधान है कि इसमें शामिल किसी भी चीज़ को

[4] ए आई आर 1961 अस सी 112

महामहिम या गवर्नर-जनरल के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाला नहीं माना जाएगा, जब उन्हें सजा को क्षमा करने, राहत देने, या छूट देने का अधिकार सौंपा गया हो। यह स्थिति संविधान लागू होने तक जारी रही। क्षमादान से संबंधित पूर्व शाही विशेषाधिकार को कवर करने के लिए संविधान में दो प्रावधान पेश किए गए थे, और वे अनुच्छेद 72 और 161 हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने, माफ करने की शक्ति से संबंधित है। या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा कम करना। अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ अपराधों के संबंध में समान शक्ति देता है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। संहिता की धारा 401 और 402 को अनुच्छेद 72 और 161 के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ जारी रखा गया था। हालाँकि, यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 72 और 161 न केवल क्षमा और राहत से संबंधित हैं जो शाही विशेषाधिकार के भीतर थे, बल्कि ये भी हैं इसमें वह शामिल है जो संहिता की धारा 401 और 402 में प्रदान किया गया है..... "

17. विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील पूरी तरह से अस्थिर है और इसकी अस्थिरता उस निर्णय से किसी भी तरह से कम नहीं होती है जिस पर विचार करने के लिए विद्वान वकील ने हम पर दबाव डाला है। उनका आधिपत्य यह कहते हुए कि संहिता की धारा 401 और 402 के प्रावधान (जिन्हें संशोधित संहिता में धारा 432 और 433 के रूप में कुछ संशोधनों के साथ पुनर्जन्म दिया गया है) को धारा 72 और 161 के प्रावधानों के अनुरूप लाया गया है। भारत के संविधान से दूर-दूर तक यह संकेत नहीं मिलता कि संहिता के ये प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित शक्तियों का प्रक्षेपण हैं। संहिता की धारा 432 और 433 के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। भले ही उपरोक्त दो अनुच्छेदों को भारत के संविधान से हटा दिया जाए, धारा 432 और 433 के प्रावधान, और धारा 434 के मामले में, संहिता को अवैध या असंवैधानिक नहीं बनाया जाएगा और राज्य सरकार या केंद्र सरकार जारी रहेगी उक्त प्रावधानों के आधार पर इसमें निवेश की गई शक्तियों का आनंद लेना। यदि भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों को भारत के संविधान से मिटा दिया जाता है, तो इसका परिणाम केवल भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति से उन शक्तियों को छीनना होगा जो वे अब उन प्रावधानों के आधार पर प्राप्त करते हैं।

18. विद्वान वकील ने फिर भी तर्क दिया कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 3(60) और धारा 3(8) में दी गई क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परिभाषा के आधार पर, अनुच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्यपाल' 161 और भारत के संविधान के

अनुच्छेद 72 में प्रयुक्त 'भारत के राष्ट्रपति' को क्रमशः राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रूप में समझा जाना चाहिए और, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 से मिलने वाली शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्वान वकील ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम[5], मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अपनी उपरोक्त दलील को रेखांकित करने की मांग की।

19. उनके आधिपत्य के समक्ष मामले में, जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें से एक यह था कि क्या राज्य सरकार असंशोधित न्यायालय की धारा 561-ए के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का चालान कर सकती है। वह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय ने पूरे पुलिस बल के खिलाफ कुछ व्यापक टिप्पणियाँ की थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि राज्य को पीड़ित पक्ष नहीं माना जा सकता। यह उस प्रश्न के संदर्भ में था कि उनकी लॉर्ड्रशिप्स ने राज्य सरकार की परिभाषा को संदर्भित किया था, जैसा कि 1897 के सामान्य खंड अधिनियम में उल्लिखित है, और यह नहीं कि उन्होंने 'गवर्नर' की अभिव्यक्ति के संबंध में कोई विवाद तय किया था। भारत का संविधान 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति के साथ विनिमेय है।

20. भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 और 154 के प्रावधानों के आधार पर, संघ और संपत्ति सरकारों की कार्यकारी शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित है और जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 और 166 द्वारा निर्धारित है। संघ और राज्य सरकारों की कार्यकारी कार्रवाइयां क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर की जाएंगी, और इसलिए, जब भी कोई कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है या किया जाना व्यक्त किया जाता है, तो वह उनके आधिपत्य द्वारा संदर्भित और याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील द्वारा भरोसा की गई परिभाषा के आधार पर, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कार्रवाई के समान है: लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां भी संविधान में 'राज्यपाल' या 'राष्ट्रपति' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह अभिव्यक्ति 'राज्य सरकार' या 'संघ सरकार' अभिव्यक्ति के साथ विनिमेय है और कोई 'राज्यपाल' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति पढ़ सकता है। या 'राष्ट्रपति' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'केंद्र सरकार/भारत सरकार'। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संहिता की धारा 432, 433 और 434 के संदर्भ में राज्य या केंद्र सरकार की शक्ति, भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 और 72 के तहत भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति में निहित शक्ति से उत्पन्न होती है।

21. हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मलिक ने यह तर्क देने की कोशिश की कि चूंकि, जैसा भी मामला हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 161 और

[5] ए आई आर 1964 अस सी 703

72 में निहित अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। भारत, जैसा भी मामला हो, अपने मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 166(2) और 77(2) के तहत बनाए गए व्यवसाय के नियमों पर निर्भर करता है और इसलिए, प्रतिबंध लगाया जाता है। सजा कम करने और छूट देने के मामले में संहिता की धारा 433-ए द्वारा धारा 432 और 433 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगी, क्योंकि इससे किसी भी शक्ति का नुकसान नहीं होगा। सरकार में से कोई भी, जो संहिता की धारा 432 और 433 के तहत नहीं कर सकता, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत, जैसा भी मामला हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति के माध्यम से कर सकता है।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रयास किया; संधवालिया, न्यायमूर्ति,' (जैसा कि वह तब था) के निम्नलिखित अवलोकनों से अपने उपरोक्त कानूनी रुख को मजबूत करने के लिए, जिन्होंने पंजाब राज्य बनाम ओम प्रकाश धरवई और अन्य[6], में बेंच के लिए बहुमत की राय दी थी।

> "इसलिए, विधायी इतिहास, संवैधानिक अधिकारियों की सर्वसम्मत राय और सुप्रीम कोर्ट की बाध्यकारी टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में देखता है जो मुख्य रूप से उसकी सलाह पर कार्य करता है।" मंत्रिपरिषद: मंत्रिपरिषद और ऐसी सलाह का क्षेत्र सर्वव्यापी है, सीमांत और दुर्लभ मामलों को छोड़कर जो केवल अपवाद की प्रकृति के होते हैं जो नियम को साबित करने के लिए जाते हैं: राष्ट्रपति केवल अपने कैबिनेट की सलाह से कार्य करता है। हालाँकि, जहाँ शक्ति की प्रकृति ऐसी है कि इसका प्रयोग संभवतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं किया जा सकता है, तभी राष्ट्रपति अन्यथा कार्य कर सकता है। इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है जहां उन्हें आम चुनाव के बाद प्रधान मंत्री चुनने के लिए कहा जाता है। जाहिर है ऐसी स्थिति में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम नहीं कर सकते। हालाँकि, इस स्थिति में भी उनका कथित विवेक, गहराई से सीमित है और स्थापित परंपरा से बंधा हुआ है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाना होगा और उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में नामित करना होगा। हमारे उद्देश्य के लिए, उन शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देना आवश्यक नहीं है जिनमें राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करना पड़ सकता है। हालाँकि, इस अपरिहार्य निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि हमारे संविधान के तहत जहां तक राष्ट्रपति का संबंध है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश या आधार नहीं है कि राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक या व्यक्तिगत

[6] 1973(1) अस अल आर 135

निर्णय में किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसी शक्तियां भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्पष्ट रूप से गवर्नर-जनरल में निहित की गई थीं और संविधान का मसौदा तैयार करते समय संघ संविधान समिति द्वारा इन शक्तियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और बाहर रखा गया था। संविधान सभा संघ का, अर्थात्, ऐसी किसी शक्ति का भारत का राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और आवश्यक निहितार्थ से कार्यकारी प्रमुख को अस्वीकार कर दिया। दो महान संवैधानिक प्रणालियों, अर्थात् ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान, जिनसे हमारे संविधान के संस्थापकों ने प्रेरणा ली, की तुलना करने पर कहा गया था कि इंग्लैंड का राजा शासन करता है, लेकिन शासन नहीं करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन नहीं करता है। शासन करते हैं लेकिन भारत के राष्ट्रपति न तो शासन करते हैं और न ही शासन करते हैं। घरेलू शब्दों में यह कहावत एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को सही मायने में व्यक्त करती है।

क्या संघ के राज्यों के कार्यकारी प्रमुख अर्थात् राज्यपाल में निहित शक्तियों के संबंध में स्थिति कोई भिन्न है? उत्तर फिर से लगभग उसी शब्द में प्रतीत होता है जैसा कि यह संघ के प्रमुख, अर्थात् राष्ट्रपति के मामले में है। संविधान संघ और राज्य कार्यकारिणी से अलग-अलग व्यवहार करता है, लेकिन दोनों अध्यायों, अर्थात् भाग V के अध्याय I और भाग VI के अध्याय 2 में प्रावधान एक सामान्य पैटर्न का पालन करते हैं और ज्यादातर मामलों में संघ और राज्य के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ समान हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकारी कार्यों से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन और तुलना विभिन्न बिंदुओं पर पहचान नहीं तो करीबी समानता दिखाती है। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की छवि में ढाला गया है और वास्तव में उसके पास अधिक सीमित शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल एक निर्वाचित प्रधान नहीं है और अनुच्छेद 155 के आधार पर वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अपनी इच्छानुसार पद पर बना रहता है। संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के तहत, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है जब वह राज्य सरकार के सभी कार्यों को स्वयं ग्रहण करता है। इस संबंध में अनुच्छेद 163(1) का संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नलिखित शब्दों में है: -

"163(1) राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब तक वह इस संविधान के तहत या इसके तहत अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक है या उनमें से कोई भी अपने विवेक पर निर्भर करता है।"

इस प्रावधान की तुलना संबंधित अनुच्छेद 74(1) से करना शिक्षाप्रद है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान में ही स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अपने विवेक से अपने किसी भी कार्य का प्रयोग करना होगा। आवश्यक निहितार्थ से, राज्यपाल के अन्य कार्यों का निर्वहन उसे अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करना होता है। इसलिए, उपरोक्त उद्धृत लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि जब तक संविधान स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है, राज्यपाल को केवल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना है जो अपने मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह का पालन करता है। बाद के प्रावधानों में, संविधान उस विशिष्ट स्थिति का प्रावधान करता है जिसमें राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से अलग कार्य करना होता है। इस संबंध में अनुच्छेद 371, उप-खंड (1) और (2) का संदर्भ दिया जा सकता है जो उस अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों के संबंध में राज्यपाल की कोई विशेष जिम्मेदारी बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रावधान करता है। पुनः अनुच्छेद 371-ए उप-खंड 1(बी) में उस स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जहां नागालैंड के राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करेंगे जो अंतिम होगा। पुनः अनुच्छेद 371-ए, उप-खंड 2(बी) और (एफ) में उन शक्तियों का उल्लेख है जिनका प्रयोग राज्यपाल को अपने विवेक से करना है। इसी प्रकार संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 9, उप-खंड (2) और पैरा 18, उप-खंड (3) में विशेष रूप से राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

■उपर्युक्त प्रावधानों को अनुच्छेद 163(1) के साथ पढ़ने पर, एकमात्र परिणाम जो सामने आता है वह यह है कि निर्दिष्ट प्रावधानों को छोड़कर जहां राज्यपाल को या तो अपने व्यक्तिगत विवेक से या अपने व्यक्तिगत निर्णय से या अपने विशेष के निर्वहन में कार्य करना है उत्तरदायित्व, उसे अपने कार्यों के शेष क्षेत्र में अपने मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना है।

23. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[7] मामले में की गई कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति की निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपने उपरोक्त कथन को सुदृढ़ करने की मांग की: -

"अपीलकर्ता के वकील का तर्क यह है कि जहां भी राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की जाती है और वही बात राज्यपाल के लिए भी लागू होती है - वह अपने आप में संप्रभु है और उसे व्यक्तिगत रूप से कार्यों का पालन करना होता है और एक प्रॉक्सी के आदेश देने होते हैं।" यहां तक कि एक मंत्री भी राष्ट्रपति की शक्ति के

[7] ए आई आर 1974 अस सी 2192

प्रयोग के लिए कर्तव्य नहीं निभा सकता। इस तर्क में तर्क है कि यदि, अनुच्छेद 311 के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल का अर्थ व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल है, तो अन्य समान अनुच्छेदों के तहत मंत्रियों और अधिकारियों को कार्यों का दायित्व सौंपने के नियम मान्य नहीं हो सकते हैं। वास्तव में, संविधान में ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश प्रशासन के दैनिक संचालन और नियमित या महत्वपूर्ण प्रकृति की कार्यकारी, आपातकालीन और विधायी शक्तियों को अपनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्षमा प्रदान करने या सजा माफ करने की शक्ति (अनुच्छेद 161), मुख्यमंत्री (अनुच्छेद 164), अधिवक्ता-जनरा1 (अनुच्छेद 165), जिला न्यायाधीश (अनुच्छेद 233), सदस्य सहित नियुक्तियाँ करने की शक्ति ? लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 316) इसी श्रेणी के हैं। इसी तरह, विधानमंडल के किसी भी सदन को स्थगित करने या विधान सभा को भंग करने की शक्ति (अनुच्छेद 174), विधानमंडल के सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार (अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 16), विधेयकों पर सहमति देने की शक्ति या ऐसी सहमति रोकें (अनुच्छेद 200), अनुदान की मांगों के लिए सिफारिशें करने की शक्ति (अनुच्छेद 203(3), और हर साल वार्षिक बजट रखने का कर्तव्य (अनुच्छेद 202), अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधानमंडल (अनुच्छेद 213) भी इसी प्रकार की शक्ति से संबंधित है। फिर, अनुच्छेद 324 (1) द्वारा प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए चुनाव आयोग को अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने का दायित्व आयोग (अनुच्छेद 324(6)) पर है। कुछ स्थितियों में एंग्लो-इंडिया समुदाय के सदस्य को विधानसभा में नामांकित करने की शक्ति (अनुच्छेद 333), उच्च न्यायालय में कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति (अनुच्छेद 348(2), कार्यों का उदाहरण हैं राज्यपाल की योग्यता।

इसी प्रकार, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेदों द्वारा व्यापक दायरे को कवर करने वाली शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं। वास्तव में, वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है (अनुच्छेद 53(2), सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और विवाद उत्पन्न होने पर न्यायाधीशों की आयु निर्धारित करता है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए प्रश्नों को संदर्भित करने की शक्ति रखता है। (अनुच्छेद 143) और यह मानने से डरता है कि किसी राज्य की सरकार को संविधान (अनुच्छेद 356) के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यपाल और लोक सेवकों की पूरी सेना पद धारण करती है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना, विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर भी कानून नहीं बन सकता। भारत के पूर्व देशी राज्यों के नियमों को मान्यता देना और उनकी मान्यता रद्द करना राष्ट्रपति में निहित

शक्ति है। अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने की असाधारण शक्तियाँ, बर्खास्तगी से पहले लोक सेवकों के खिलाफ जांच बंद करना, आपातकाल की घोषणा करना और राज्यों पर उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करना, गहन महत्व की विशाल शक्तियां हैं। वास्तव में, यहां तक कि लोगों के सदन को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने और पारित विधेयकों को वापस लेने की शक्ति भी है। संसद उनकी है, यदि हम प्रत्येक कार्य में सरदारीलाल[8] और जयंतीलाल[9] के अनुपात की व्याख्या करें जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रदान करते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र एक मादक द्रव्य बन जाएगा और राष्ट्रीय चुनाव महंगी निरर्थकता में एक संख्यात्मक अभ्यास बन जाएगा। हम यह मानने के लिए मजबूर होंगे कि देश के शासन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले दो समानांतर प्राधिकरण हैं, जैसा कि द्वैध शासन के दिनों में था, सिवाय इसके कि व्हाइटहॉल को राष्ट्रपति भवन और राजभवन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मंत्रिमंडल में संघ और राज्य स्तरों पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार कम हो जाएंगे और, अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, राज्य का प्रमुख भारत के महामहिम राज्य सचिव का पुनर्जन्म होगा, यहां तक कि ब्रिटिश भी इससे अछूते रहेंगे। संसद-शक्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति से थोड़ी बड़ी। इस तरह की विकृति, व्याख्या से हमें ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुतः हमारे गणतंत्र की संरचना, सार और जीवन शक्ति का विध्वंस होगा, खासकर जब हम याद करते हैं कि राज्यपाल केवल नियुक्त पदाधिकारी हैं और राष्ट्रपति स्वयं सीमित अप्रत्यक्ष आधार पर चुने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, इस न्यायालय के अधिकारियों की भारी संख्या ने दशकों से यह स्थापित किया है कि भारत में कैबिनेट सरकार और संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और इसके विपरीत अवधारणा को हमारी राजनीतिक प्रतिभा, संवैधानिकता, पंथ और संस्कृति के प्रति अविश्वसनीय रूप से खतरनाक मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

24. ओम प्रकाश धरवाल और अन्य के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के समक्ष और समशेर सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य के समक्ष पेश किए गए अत्यधिक विवाद की जांच करते समय उपरोक्त टिप्पणियां की गईं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, जैसा भी मामला हो, कार्यकारी मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा, विधायी मामलों में विधायिका द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी सलाह से स्वतंत्र होकर, अपने स्वयं के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपने संवैधानिक कार्यों का

[8] (1971)3 एस.सी.आर. 461 = 1971 एस.सी. 1547.

[9] (1964)5 एस.सी.आर. 294 = (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 648)

प्रयोग करें। मामला न्यायिक मामलों में हो सकता है। लेकिन एक मामले में उच्च न्यायालय और दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, उसमें से किसी भी न्यायालय का यह कहना नहीं समझा जा सकता है कि संघ या राज्य सरकार में कुछ क़ानूनों द्वारा निहित शक्तियाँ इसके साथ मिलती हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रदत्त समान शक्तियाँ। हमारी राय में, दोनों शक्तियां अलग-अलग हैं और अलग-अलग रहेंगी। अंतर, हालांकि कमजोर है, दो शक्तियों के प्रयोग में निहित है, क्योंकि किसी दिए गए मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग वैध रूप से किसी भी मंत्री या अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे इसके द्वारा बनाए गए व्यवसाय के नियमों के तहत सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल इसे केवल राज्यपाल के नाम पर व्यक्त करते हैं, लेकिन राज्यपाल को मामले का कोई वास्तविक संदर्भ नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे मामले में जहां संविधान या क़ानून राज्यपाल या राज्यपाल को कुछ शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद या मंत्री या व्यवसाय के नियमों के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कार्य करने के लिए अधिकृत अधिकारी को, मामले के अनुसार, राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपनी सलाह के साथ मामले पर विचार करने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है, तब भी जब उपरोक्त दो निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

25. अब मंच उस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने के लिए तैयार है जिसे श्री मलिक ने संहिता की धारा 433-ए के आवेदन के परिणामस्वरूप होने वाले घृणित भेदभाव से संबंधित कुछ जोरदार तरीके से प्रचारित किया है। अपने कथन को उजागर करने के लिए, विद्वान वकील एक काल्पनिक मामले का हवाला देते हैं जहां छह व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जो मौत से दंडनीय है। जिसके हिस्से में महज ललकारा देने की मामूली बात थी, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई; अन्य पांच जिन्होंने घातक वार किए थे और अपराध में गंभीर भूमिका निभाई थी, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, उनमें से दो गर्भवती महिलाएं थीं और बाकी पुरुष थे। एक गर्भवती महिला की सज़ा को अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 416 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया था - हो सकता है कि दूसरी की गर्भावस्था स्पष्ट न हो और जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने राज्य सरकार से क्षमादान और मौत की सज़ा के लिए आवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा धारा 433(ए) के तहत परिवर्तित कर दिया गया था। तीसरे ने दया के लिए राज्यपाल के पास आवेदन किया और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। चौथे की सज़ा को न तो सरकार ने और न ही राज्यपाल ने कम किया। उन्होंने केंद्र सरकार को आवेदन दिया और केंद्र सरकार ने संहिता की धारा

434 के तहत उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। पांचवें ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दया याचिका प्रस्तुत की, जिन्होंने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

26. संहिता की धारा 433-ए के लागू होने के परिणामस्वरूप, जेल अधिनियम और कार्यकारी निर्देशों के तहत बनाए गए मौजूदा नियमों के मद्देनजर, उपरोक्त छह दोषी कैदियों को वास्तविक कारावास की अलग-अलग सजा भुगतनी होगी। जबकि उन लोगों के मामले में जिनकी मौत की सजा को राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और न्यायालय ने क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 और संहिता की धारा 434 और 416 के तहत कम कर दिया था, धारा 432 के प्रावधान संहिता लागू होगी और राज्य सरकार उन्हें जेल अधिनियम के तहत बनाए गए मौजूदा नियमों और कार्यकारी निर्देशों के अनुसार रिहा करने के लिए खुली होगी, जब वे वास्तव में चौदह साल से कम समय तक जेल में रहे हों, जबकि जो व्यक्ति जेल में था। अदालत द्वारा ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जिसकी मौत की सजा को किसी भी सरकार द्वारा संहिता की धारा 433 (ए) के तहत बदल दिया गया था, उसे तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वे वास्तव में चौदह साल की अवधि के लिए जेल में न रह गए हों। विद्वान वकील ने एक और विसंगति पर प्रकाश डाला जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जिस व्यक्ति को अपराध में उसका हिस्सा बहुत छोटा होने के कारण अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसे वास्तव में चौदह साल तक जेल में रहना होगा। लेकिन अन्य, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी - उनका हिस्सा गंभीर था - और उनकी मौत की सजा को संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत आजीवन कारावास में बदला जा रहा था, उन्हें बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के तहत रिहा किया जा सकता था। चौदह वर्ष की वास्तविक जेल अवधि से गुज़रे बिना, जेल अधिनियम या कैदी अधिनियम और जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए मैनुअल में सन्निहित कार्यकारी निर्देश।

27. उपरोक्त पैराग्राफ में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील जिन नियमों और कार्यकारी निर्देशों से हमें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, वे निम्नलिखित हैं:

जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधान।

> “631. (1) ये नियम ब्रिटिश बलूचिस्तान और सोंथल परगना सहित पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू होते हैं।
>
> (2) इन नियमों में-
>
> (ए) 'कैदी' में शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने में चूक करने पर जेल भेजा गया व्यक्ति शामिल है;

(बी) 'श्रेणी I कैदी' का अर्थ है ठग, जहरीली दवाएं देने वाला लुटेरा या डकैती जैसे जघन्य संगठित अपराध का दोषी पेशेवर, वंशानुगत या विशेष रूप से खतरनाक अपराधी;

(सी) 'वर्ग 2 कैदी' का अर्थ है एक डकैत या जघन्य संगठित अपराध का दोषी अन्य व्यक्ति, जो पेशेवर, वंशानुगत या विशेष रूप से खतरनाक अपराधी नहीं है;

(डी) 'वर्ग 3 कैदी' का अर्थ वर्ग 1 या वर्ग 2 के कैदी के अलावा कोई अन्य कैदी है;

(ई) 'सजा' का अर्थ अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा पर अंतिम रूप से तय की गई सजा है, और इसमें एक से अधिक सजाओं का योग और शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने में चूक करने पर जेल भेजने का आदेश शामिल है;

(एफ) 'आजीवन दोषी' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी सजा 20 साल की कैद के बराबर है;

(i) श्रेणी 1 या श्रेणी 2 का कैदी जिसकी सजा पच्चीस साल की कैद है, या

(ii) श्रेणी 3 का कैदी जिसकी सजा बीस साल की कैद की है।

नोट.-सभी आजीवन-दोषियों और 14 वर्ष से अधिक कारावास या परिवहन और कुल 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पाने वाले सभी कैदियों के मामले में, कारावास की अवधि पूरी होने पर, इसके तहत अर्जित किसी भी छूट के साथ गृह विभाग के संकल्प संख्या 159-67 (जेल), दिनांक 6 सितंबर, 1905 में निहित निर्देशों के अनुसार स्थानीय सरकार के आदेशों के लिए प्रस्तुत किए गए नियमों की अवधि, जैसा भी मामला हो, 10 या 14 वर्ष है।

* * * * *

645. इन सभी नियमों के तहत किसी कैदी को दी गई कुल छूट, स्थानीय सरकार की विशेष मंजूरी के बिना, उसकी सजा के एक-चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि बहुत ही असाधारण और उपयुक्त मामले में, जेल महानिरीक्षक कुल सजा के एक तिहाई से अधिक की छूट नहीं दे सकता है।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

647. (1) जब कोई आजीवन कारावास का दोषी हो -

(ए) प्रथम श्रेणी का कैदी, या

(बी) एक से अधिक सजा वाला द्वितीय या तृतीय श्रेणी का कैदी,

(सी) एक कैदी जिसके मामले में स्थानीय सरकार ने बिना किसी संदर्भ के उसकी रिहाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है, उसने ऐसी छूट अर्जित की है जो उसे रिहाई का अधिकार देगी लेकिन इस पैराग्राफ के प्रावधानों के लिए, अधीक्षक स्थानीय सरकार को तदनुसार रिपोर्ट करेगा। कि उनके मामले पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।

(2) खंड (1) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, जब किसी कैदी ने ऐसी छूट अर्जित कर ली है जो उसे रिहा करने का हकदार बनाती है तो अधीक्षक उसे रिहा कर देगा।

28. इस स्तर पर प्रचारित बिंदु से निपटने से पहले, संहिता की धारा 433-ए के दायरे की जांच की आवश्यकता है ताकि उन प्रावधानों को निर्धारित किया जा सके जो इसके प्रतिबंधात्मक दायरे में लाए गए हैं। ए! संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों का अवलोकन, जो पहले ही ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है, हमारी राय में, यह दिखाएगा कि धारा 416 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा किया गया परिवर्तन भी धारा 433-ए के प्रावधानों से प्रभावित होता है। संहिता की धारा 433-ए का पहला भाग उन मामलों को शामिल करता है जहां मौत की सजा वाले अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जहां तक अदालतों का सवाल है, उनका कार्य सज़ा देना है - वे एक सज़ा के स्थान पर दूसरी सज़ा दे सकते हैं। न्यायालयों द्वारा सज़ा का प्रतिस्थापन, भले ही इसे कम्यूटेशन के रूप में वर्णित किया गया हो, हमारी राय में, प्रतिस्थापित सज़ा लगाने के समान होगा और इसलिए; जब भी अदालतें धारा 416 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में बदलती हैं, तो उन्हें उस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा देना समझा जाना चाहिए जो मौत की सजा से दंडनीय है। और तदनुसार एक दोषी का मामला जिसका; संहिता की धारा 416 के तहत न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना संहिता की धारा 433-ए के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के दायरे में आता है।

29. जहां तक संहिता की धारा 434 का संबंध है, स्थिति अलग नहीं है। संहिता की धारा 434 इस प्रकार है: -

"434. मौत की सजा के मामले में राज्य सरकार को धारा 432 और 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

धारा 434 के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि मौत की सजा के मामले में केंद्र सरकार के पास, भले ही वह उपयुक्त सरकार न हो, उसके पास वही शक्तियाँ हैं जो कोड कि धारा 432 और 433 के तहत राज्य सरकार के पास हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 433-ए स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 432 और 433 के तहत प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की शक्ति के दायरे को प्रतिबंधित करती है, और चूंकि धारा 434 के तहत केंद्र सरकार को उस शक्ति के बराबर शक्ति मिलती है जिसका आनंद राज्य सरकार को मिलता है। धारा 432 और 433, इसलिए धारा 434 के तहत इसकी शक्ति तदनुसार धारा 433-ए के प्रावधानों द्वारा सीमित है और इसलिए, ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देती है, दोषी-कैदी को उसके पहले रिहा नहीं किया जा सकता है। चौदह वर्ष की वास्तविक कारावास की सज़ा पूरी कर ली है।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भेदभाव का प्रश्न उन मामलों से संबंधित है जहां किसी दोषी की सजा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कम कर दी जाती है, जबकि उन लोगों की तुलना में जिनकी मौत की सजा संहिता की धारा 433 या 434 या 415 के तहत कम कर दी गई है।

31. इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 433-ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित संवैधानिक शक्तियों पर न तो कोई सीमा लगाती है और न ही यह कोई सीमा लगा सकती है। लेकिन इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिणामी भेदभाव ऐसा होगा जो संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के विरुद्ध खड़ा कर देगा।

32. अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तब उत्पन्न होता है जब राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करता है। यहां ऐसा मामला नहीं है। जिन दोषियों की मौत की सजा को, जैसा भी मामला हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अपनी परिणामी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बदल दिया जाता है, वे उन लोगों के अलावा एक वर्ग से संबंधित होते हैं जिनकी मौत की सजा को वैधानिक प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। पहले ही उल्लेख किया गया है, और इसलिए, संहिता की धारा 433-ए के प्रावधानों को असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

33. विषम स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब संहिता की धारा 433-ए के लागू होने के परिणामस्वरूप एक दोषी जिसका हिस्सा नाबालिग था और जिसे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा देना उचित समझा, उसे वास्तविक अवधि से कम नहीं बिताना होगा चौदह वर्ष जेल में, जबकि दूसरे को, जिसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और उसकी मौत की सजा को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा कम कर दिया गया था, चौदह वर्षों

की वास्तविक जेल अवधि से पहले पूर्व श्रेणी के दोषी को समय से पहले रिहा करके इसका समाधान किया जा सकता है।

34. हमें विश्वास है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत क्रमशः अपनी छूट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य और केंद्र सरकार संहिता की धारा 432 और 433 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। उक्त विसंगति को ध्यान में रखें, क्योंकि उनके हाथों को रिहा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि गोपाल विनायक गोडसे के मामले (सुप्रा) में और बाद में रतन सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में उनके आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कानूनी स्थिति यह है कि आजीवन कारावास का अर्थ आजीवन कारावास है और कोई भी दोषी कैदी, जेल अधिनियम या कैदी अधिनियम या कार्यकारी निर्देशों के तहत बनाए गए किसी भी नियम के आधार पर, ऐसे नियमों या निर्देशों में उल्लिखित किसी भी निश्चित अवधि की समाप्ति पर रिहा होने का दावा नहीं कर सकता है। , और, इसलिए, आखिरकार, एक दोषी कैदी जिसकी मौत की सजा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, उसे चौदह साल की वास्तविक कैद से पहले रिहा किया जाना चाहिए या नहीं, यह पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा। ऐसे किसी भी कैदी की रिहाई का आदेश देने के लिए कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी का।

35. उल्लिखित कारणों से, हम मानते हैं कि संहिता की धारा 433-ए की संवैधानिकता के खिलाफ हमला विफल है और इन रिट याचिकाओं (सिविल रिट संख्या 2089 और 2167, 1979) में कोई योग्यता नहीं पाते हुए हम इसे खारिज करते हैं।

माननीय मुख्य न्यायधीश श्री एस.एस. संधावालिया, - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा